

### चालू करना

“क” \*155. श्री संतोष कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड वायसी के बनगामा पंचायत के भरवा ग्राम में विगत तीस वर्षों से खादी ग्रामोद्योग चल रहा था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खादी ग्रामोद्योग विगत 10 वर्षों से बंद है, जिससे सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर हैं एवं बेरोजगार हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खादी ग्रामोद्योग को चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### चीनी मिल चालू करना

\*422. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चकिया चीनी मिल 1906 ई० से शुरू होकर 1994 ई० में बन्द हो गया, चीनी मिल के बन्द होने से पूरे इलाके के किसानों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर एवं जर्जर हो गयी है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चकिया चीनी मिल को कबतक चालू करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

### कारा का निर्माण

\*423. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा को अनुमंडल बने हुए 17 वर्ष बीत गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि मढ़ौरा अनुमंडल मुख्यालय में अभीतक उप-मंडल कारा की स्थापना नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मढ़ौरा अनुमंडल मुख्यालय में उप-मंडल कारा का निर्माण करने हेतु कौन-सी कार्यवाई करने का विचार रखती है ?

### पुलिस चौकी का निर्माण

\*424. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दरियापुर थाना क्षेत्र की लम्बाई लगभग 25 कि०मी० है एवं आबादी लगभग 90 हजार है;

(2) क्या यह बात सही है कि दरियापुर थाना का उत्तरी भाग एक मात्र थाना से नियंत्रित नहीं हो पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार थाना के उत्तरी भाग के ग्राम-दरिहाग में पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

“क”--दिनांक 28 फरवरी, 2011 को सदन द्वारा स्थगित ।

## सुविधा बहाल करना

\*425. डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर, गौरा बौराम एवं बिरौल प्रखंड में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एम०सी०डी० योजना से अभी तक पूर्ण रूप से पेयजल सुविधा एवं इन्दिरा आवास से आच्छादित नहीं हो पाया है, जिससे उनके समक्ष पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है, यदि हां, तो क्या सरकार कबतक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एम०सी०डी० योजना से बुनियादी सुविधा बहाल करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## कमरों का निर्माण

\*426. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत धमौल थाना, बाजार के बीच धनी आबादी में जर्जर भवन में चल रहा है, बरसात में छत से पानी चू जाने से महत्वपूर्ण कागजात बर्बाद हो गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि धमौल बाजार से आधा कि०मी० दक्षिण आवा-शेखपुरा मार्ग से सटे थाना का नया भवन वर्ष 2005 से बनकर तैयार है, परन्तु पुलिस बैरक, घेराबन्दी एवं पेयजल की सुविधा नहीं रहने के कारण नया भवन में थाना स्थानान्तरित नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धमौल थाना को नया भवन के घेराबन्दी एवं अतिरिक्त कमरे का निर्माण करवाकर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## रिक्त पदों को भरना

\*427. श्री जितेन्द्र कुमार राय--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 9 जनवरी, 2011 के अंक में प्रकाशित खबर के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अभी भारतीय पुलिस सेवा के 72 पदाधिकारियों के पद रिक्त हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है और अधिकारियों की कमी के कारण राज्य में बढ़ते नक्सलवाद एवं अपराध को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 72 पदाधिकारियों के पदों को रिक्त रखने का क्या औचित्य है ?

## ओ०पी० का निर्माण

\*428. श्री प्रमोद कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत मधुबनी घाट, बरदाहा, डेकहा, उ० डेकहा, प० डेकहा, द० डेकहा, सिरसा ये सातों पंचायत के बीचोबीच डेकहा बाजार स्थित है, जो सर्वाधिक एम०सी०सी० प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, जहां से थाना की दूरी लगभग 15 कि०मी० दूर मोतिहारी शहर के अधीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना को दूर रहने के कारण इस एम०सी०सी० प्रभावित क्षेत्र में आमजन की सुरक्षा में भारी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार डेकहा बाजार पर ओ०पी० बनाने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?



## छात्रावास का निर्माण

\*429. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि किसानगंज जिलान्तर्गत ठाकुर गंज एवं दिघल बैंक प्रखंडों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं है;
- (2) क्या यह बात सही है कि छात्रावास नहीं रहने के कारण यहां के छात्रों को एक लम्बी दूरी तय कर स्कूल एवं कॉलेज आना-जाना पड़ता है जिससे छात्र परेशान हो जाते हैं;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ठाकुरगंज एवं दिघल बैंक प्रखंडों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## दोषियों पर कार्रवाई

\*430. श्री सुरेश बंधल--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि समाहरणालय, मुजफ्फरपुर में वर्ष 1994 में बैकलॉग के आधार पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के चतुर्थवर्गीय दैनिकभोगी कर्मचारियों के 1064 पद का पैनेल तैयार किया गया;
- (2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2001 में पुनः एक पैनेल तैयार किया गया, जिसमें उक्त पैनेल के सभी व्यक्तियों का नाम सम्मिलित था;
- (3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003 में समाहरणालय, मुजफ्फरपुर में उक्त पैनेल को छोड़कर केवल 84 सामान्य कोटि के व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गयी जो आरक्षण नियमों का उल्लंघन है;
- (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## नियुक्ति करना

\*431. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने 10 हजार अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया था;
- (2) क्या यह बात सही है कि इसके लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन भी निकाला गया तथा नियुक्ति के लिए चार लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु एक वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक आवेदनों को स्क्रूटनी भी नहीं हुई है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेरोजगार युवकों के हित में कबतक विज्ञापित पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

## बैंक शाखा खोलना

\*432. श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक "बैंकिंग सुविधा में भी पिछड़ा है बिहार" की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए क्या मंत्री, वित्त वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बैंक शाखा खोलने हेतु राष्ट्रीय औसत 15000 की आबादी पर एक बैंक शाखा खोलने का मानक तय है जबकि बिहार में मानक के विपरीत 22500 आबादी पर एक बैंक है;
- (2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखा के अभाव में पैक्स, किराना दुकानदार, जनवितरण प्रणाली के दुकानदार, रिटायर कर्मचारी एवं सहकारिता समूहों को बैंकिंग कारोबार में कठिनाई होती है;
- (3) क्या यह बात सही है कि मानक के अनुसार बैंकिंग सुविधा नहीं रहने के कारण बिहार राज्य को पिछड़ने का भी एक कारण मौजूद है;
- (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राष्ट्रीय मानक के अनुसार कुल 2300 बैंक शाखा और खोलने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक ?

## बकाना का भुगतान

\*433. श्री रामायण मांझी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के किसानों के द्वारा प्रतापपुर चीनी मिल में दिए गये गन्ना का भुगतान नहीं की गयी है;
- (2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत किसानों को 2006-07 में गन्ना खोस देनी थी, जो अभी तक नहीं दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीवान जिला के किसानों का बकाया तथा बोनस का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

#### अनुपात में आरक्षण

\*434. श्री सोनेलाल हेम्ब्रम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत का गजट संख्या 10, दिनांक 8 जनवरी, 2003 को बिहार राज्य में थारू, कांवर, कोल जातियों को क्रमांक 30, 31, 32 में अनुसूचित जन-जाति में सम्मिलित किया गया है, इसी प्रकार गौर एवं गौड़ जाति को भी 27 फरवरी, 2007 को गौड़ जन-जाति में सम्मिलित किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुरूप पंचायत में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायत चुनाव 2011 में इन जन-जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

#### किसानों को कं०सी०सी० देना

\*435. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, पित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत कं०सी०सी० (किसान क्रेडिट कार्ड) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 28000 किसानों को कं०सी०सी० दिया जाना था;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में केवल 7273 किसानों को ही 31 दिसम्बर 2010 तक कं०सी०सी० का लाभ दिया जा सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज जिला में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों को कं०सी०सी० देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

#### अग्निशामक यंत्र रखना

\*436. श्री छोटे लाल राय--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड परसा एवं दरियापुर में अग्निशामक यंत्र नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय छपरा में ही अग्निशामक यंत्र है;

(3) क्या यह बात सही है कि किसी तरह के अग्नि घटना में जिला मुख्यालय से अग्निशामक यंत्र को आने में 3 से चार घंटा लग जाती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखण्ड दरियापुर एवं परसा में अग्निशामक यंत्र रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

#### कार्रवाई करना

\*437. श्री अख्तरूल ईमान--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र मे दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक "70 हजार वोट गायब" के आलोक में क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में जिला-सीवान के 1.30 लाख, मुंगेर के 85 हजार, गोपालगंज के 70 हजार, पटना के 70 हजार, बांका के 44 हजार मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वृथ लेबल ऑफिसर से लेकर वरीय पदाधिकारी तथा सूची तैयार करने वाले एजेंट को लापरवाही से मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कर्मियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

#### मॉडल धाना की व्यवस्था

\*438. श्री प्रमोद कुमार--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी नगर स्थित नाका नं०-1 एवं 2 शहर के लगभग 50 प्रतिशत आबादी के बीचो-बीच है जहां आरक्षी बल एवं पदस्थापित अवर निरीक्षक के रहने की व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से उसकी चहारदीवारी एवं महिला एवं पुरुष कैदीखाना नहीं रहने के कारण आय दिन शहर के आबादी के रक्षा की दृष्टि से आरक्षी बल पदस्थापित नहीं हो पाते हैं;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो नाका नं०-1 एवं 2 के जीर्ण-शीर्ण भवनों को मॉडल धाना के रूप में व्यवस्था कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?



## राशि की वसूली

\*439. श्रीमती गृहणी देवी—दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 6 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित विज्ञापन "कंपनियों पर 1.59 करोड़ बकाया" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन का व्यापार करने वाली 27 बड़े बकायेदार को पास वित्तीय वर्ष 2007 से 2010 तक 1.59 करोड़ रुपया बाकी है;
- (2) क्या यह बात सही है कि 36 एजेंसी की सचिका अंकेक्षण के लिए मांगी गयी है, जो निगम ने अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नगर निगम के उक्त विज्ञापन एजेंसियों पर बकाये को राशि वसूल करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## उद्योग लगाना

\*440. श्री मो( आफाक आलम--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत श्रीनगर, कसबा, जलालगढ़ एवं के( नगर प्रखण्ड में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर होती है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में मक्के पर आधारित उद्योग नहीं होने के कारण किसानों को मक्के का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में मक्के पर आधारित उद्योग लगाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## कार्रवाई करना

\*441. श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार के धन पर चमक रहे दूसरे प्रदेश" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के लोगों ने बैंकों में 1,01,761 करोड़ रुपये जमा पिछले वित्तीय वर्ष में कराये हैं जबकि अभी तक राज्य के लोगों को मात्र 31,921 करोड़ रुपये ही कर्ज दिये गए हैं;
- (2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में विकास का माहौल बदला है परन्तु बैंकों का रकबा नहीं बदलने की वजह से कर्ज नहीं दिया जा रहा है;
- (3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की जनता एवं विकास के हित में जमा राशि के विरुद्ध कर्ज नहीं देने वाले बैंकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## भवन उपलब्ध कराना

\*442. श्री अरुण शंकर प्रसाद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी थाना की अधिसूचना का 30 वर्ष से ज्यादा हो रहा है, जो भारत और नेपाल के सीमा पर अवस्थित है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना 5 सर्किल का है, जिसके पास आज तक अपनी भूमि और भवन नहीं है जिससे अपराध नियंत्रण में काफी कठिनाई हो रही है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बासोपट्टी थाना के लिए भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने का विचार कबतक रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

## स्थानांतरित करना

\* 443. श्री नीरज कुमार सिंह--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय में कारा भवन एक वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हो गया है, परन्तु अभी तक उसमें कैदियों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक वीरपुर जेल भवन में कैदियों को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?

## उद्योग लगाना

\* 444. डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक उच्च विद्यालय में छात्र-छात्राओं के बीच प्रतिवर्ष 5 लाख साईकिल वितरण किया जा रहा है;
- (2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार में साईकिल उद्योग लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

## कार्रवाई करना

"ख"--\* 445. श्री जनार्दन मांझी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बांका जिला की स्थापना वर्ष 1990 में की गई;
- (2) क्या यह बात सही है कि बांका जिला में जिला जज का पद लगभग 20 वर्षों से रिक्त है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बांका जिला में जिला जज की नियुक्ति करने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

## मिल चालू करना

\* 446. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 में सभी बन्द चीनी मिल को चालू करवाने का निर्णय लिया गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत चारिसलीगंज स्थित चीनी मिल वर्ष 1993 से बन्द है;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चारिसलीगंज चीनी मिल को चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

## बैंक खोलना

\* 447. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत पानापुर एवं इसुआपुर में एक भी व्यावसायिक बैंक नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के व्यवसायियों एवं किसानों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर व्यावसायिक बैंक खोलवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

"ख" विधि विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित।

## चीनी मिल चालू करना

\* 448. श्री विक्रम कुंवर--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिले में पचरुखी बाजार सहित दो अन्य चीनी मिल है, जो 1980 से बन्द है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसान हित में उक्त दोनों चीनी मिल को चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

पटना:  
07 मार्च, 2011 (ई०)

गिरिश झा,  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान-सभा।